परिचर्चा में विशेषज्ञों ने कहा

देश के विकास के साथ आर्थिक परिवर्तन के लिए बजट जरूरी

रांची. आइआइएम रांची और अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप, पॉलिसी और गवर्नेंस सेंटर फॉर एक्सिलेंस की ओर से मंगलवार को 'केंद्रीय बजट 2022-23' पर चर्चा हुई. पैनल डिस्कशन में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की डॉ मौसमी दास, नीति आयोग के हेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डॉ बदरी नारायण गोपालकृष्णन, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनांस सह एडीआरआइ के एसोसिएट प्रो डॉ सुधांशु कुमार और एनआइपीएफपी की प्रो लेखा चक्रवर्ती शामिल हुए. आइआइएम रांची की प्रो साक्षी ने केंद्रीय बजट के उद्देश्य पर अपने विचार रखे. बताया कि देश के विकास के साथ आर्थिक परिवर्तन के लिए बजट जरूरी है. इस वर्ष के बजट से देश के बुनियादी विकास को गति मिलेगी. मुख्य वक्ता डॉ बदरी नारायणन ने कहा कि देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खास क्षेत्र को चिह्नित कर उसे आइटी से जोड़ने की जरूरत है. सरकार सीमा शुल्क को कम करे तो, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इस वर्ष के बजट में सोने और हीरे के आयात शुल्क को कम करने की बात कही गयी है, इससे राजकोषीय बजट के अतिरिक्त खर्च को कम किया जा सकेगा. डॉ मौसमी दास ने कहा कि कोरोना काल ने खुदरा खर्च को बढ़ाया है. इससे घरेलू निवेश बढ़ा है. रोजगार की समस्या के कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. जबकि, अब एमएसएमइ पर ध्यान देने से इसके दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद की जा सकती है. वहीं, चर्चा में शामिल डॉ सुधांशु और प्रो लेखा ने कहा कि समय के साथ बजट सभी क्षेत्र को समान पहुंचाने का काम करेगी.

Prabhat Khabar_23.02.2022_Pg. 08